

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 6428/2022

नाहर सिंह मीणा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. शासन सचिव, गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
4. पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर (राज.)।
5. पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा (राज.)।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.12.2022

आदेश की दिनांक : 06.01.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री नरेन्द्र सिंह हाडा, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर पुलिस लाईन, भीलवाडा में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आदेश दिनांक 30.09.2022 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला भीलवाडा से जिला धौलपुर किया गया था परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 12.12.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 11.07.2017 के द्वारा अपीलार्थी को जिला अजमेर से जिला भीलवाडा पदस्थापित किया गया था, जहां पर उसने कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी के माता-पिता अधिक बीमार होने के कारण उनकी देखभाल हेतु अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय जयपुर को दिनांक 25.06.2022 को प्रस्तुत की जिसमें यह निवेदन किया है कि उसके विरुद्ध ए.सी.बी. आपराधिक मामला उदयपुर जिले में लम्बित है इसलिए उसका स्थानान्तरण नजदीकी गृह जिले धौलपुर में कर दिया जाए जिसके क्रम में प्रत्यर्थी विभाग ने उसके निवेदन पर धौलपुर स्थानान्तरण कर दिया परंतु उसे कार्यमुक्त नहीं किया

गया और आलोच्य आदेश दिनांक 12.12.2022 के द्वारा बिना किसी प्रशासनिक कारणों के उसके स्थानान्तरण आदेश को निरस्त कर दिया गया।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 12.12.2022 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कांस्टेबल के पद पर पुलिस लाईन, भीलवाडा में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश को निरस्त किए जाने का प्रश्न है। हमारे विनम्र मत में प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए. आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)